भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2382
दिनांक 03 अगस्त, 2023

सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम

2382. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) कार्यक्रम के अंतर्गत सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भरना आरम्भ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां भूमिगत भंडारण अवस्थित हैं और इनकी मिलियन मीट्रिक टन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या एसपीआर कार्यक्रम का अगला चरण सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत आरम्भ किया जाएगा और यदि हां, तो किन कंपनियों ने इस संबंध में रुचि दिखाई है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या है जहां भंडारण सुविधाएं स्थापित किए जाने की संभावना है और उनकी मिलियन मीट्रिक टन क्षमता कितनी है तथा लाभ की हिस्सेदारी किस प्रकार निर्धारित की जाएगी; और

(ङ) क्या इन भंडारों में भंडारित कच्चे तेल को अभाव की स्थिति में उपयोग किया जायेगा अथवा नियमित आधार उपयोग किया जायेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) कच्चे तेल की भूमिगत एसपीआर भंडारण की कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है और यह 2 राज्यों नामतः (i) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम (1.33 एमएमटी) (ii) कर्नाटक में मैंगलुरू (1.5 एमएमटी) और पादुर (2.5 एमएमटी) में अवस्थित हैं। अप्रैल/मई, 2020 में कच्चे तेल के निम्न मूल्यों का लाभ उठाते हुए, कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडारों को पूरी क्षमता के साथ भर लिया गया था, जिससे लगभग 5,000 करोड़ भारतीय रुपए की संभावित बचत हुई थी।

(ग) और (घ) जुलाई, 2021 में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर ओडिशा के चण्डीखोल (4 एमएमटी) एवं कर्नाटक के पादुर (2.5 एमएमटी) में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक सुविधाएँ स्थापित करने को अनुमोदित किया था।

वैश्विक व्यापारिक कम्पनियाँ यथा मेसर्स ट्रैफिगरा, बीपी, एसकेईएंडसी, पेट्रोचाइना, जीएएसपी, वोपाक, जियोस्टॉक, मोनेट, ह्युण्डाई, गल्फ एनर्जी, नेटिक्स, विटोल, ग्लेनकोर, डीबीएस, केएनओसी, मेसर्स लॉएड्स रजिस्टर, आईसी-ग्रुप, एएनयू रिसोर्सेस, शेल, पार्सन ब्रिनकरॉफ, स्वीको एबी, एसकेएएनएसकेए, आदि ने संचालित दो रोड-शो के दौरान एसपीआर परियोजना के चरण-II में प्रतिभागिता करने में रुचि प्रदर्शित की है।

पूरी सुविधा पर भारत सरकार का स्वामित्व होगा। रियायतग्राही, रियायत अवधि की 60 वर्ष की समाप्ति पर, सिंगल मूरिंग प्वॉइंट (एसपीएम), अभितट एवं अपतट पाइपलाइन के साथ एसपीआर को भारत सरकार को अंतरित करेगा।

(ङ) तेल के अभाव होने की स्थिति में कच्चा तेल लेने का प्रथम अधिकार भारत सरकार का है।

****